

प्रेषक

आर०डी०पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि प्रशासनी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2009

विषय- जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रिले) के न्यायालय हेतु
सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 29/xxxvi(1)एक/08-139-एक/2002 दिनांक 28 जनवरी 2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(रिले) के न्यायालय हेतु सृजित 09 अस्थायी संवर्गीय पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्ण सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए, दिनांक 1-3-2009 से 28-2-2010 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त न्यायालयों/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या- 38- एक (1) / न्याय विभाग/03 दिनांक 22 जुलाई, 2003 द्वारा किया गया था ।

2- उक्त न्यायालयों के कार्यालय में पद धारण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों सम्बंधित सवर्ग की सेवा नियमावली से अध्वारित होगी ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय अगामी वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजन-105-सिविल और शिशु न्यायालय-06 रिले मजिस्ट्रेट का न्यायालय-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे उल्लेखित किया जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 संपादित कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 7-11-92 (ज्या उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधित्वित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव,

संख्या- 31 (1)/xxxvi(1)एक/09-139-एक/2002समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
- 2- जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 3- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(के०पी०पाटनी)
अनु सचिव,